Issue of ration cards to slum Dwellers in the Country

3715. SHRI SHAMIM HASHMI : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state whether Government are aware that weaker sections of Society, specially the slum dwellers throughout the country are facing face difficulty in getting Ration Cards and if so corrective steps taken/proposed to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL) : Administration of Public Distribution System (PDS) including issue of ration cards is primarily the responsibility of the State Governments/U.T. Administrations. The Central Government have from time to time stressed on the need to cover the entire population specially the weaker sections of the society in all States/Union Territories under PDS. Recently an exercise was undertaken for access of jhuggi jhonpri dwellers to PDS in the Union Territory of Delhi and over 2.17 lakh such families were issued ration cards.

कृषि भूमि का क्षेत्रफल

3716. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1989-90 के अन्त तक कृषि भूमि के क्षेत्रफल को 137.8 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो 1989-90 के अन्त तक देश में कृषि योग्य भूमि का उपयुक्त क्षेत्रफल कितना था;

(घ) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नितिश कुमार) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) नवीनतम उपलब्ध भूमि उपयोग आंकड़ों के आधार पर देश में कुल कृष्ट क्षेत्र 155.7 मिलियन हैक्टेयर है ।

(घ) और (ङ) 1990-91 के दौरान कृषि के अन्तर्गत मृदा और जल संरक्षण के जरिए अधिक क्षेत्र को लाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

1. नदी घाटी परियोजना के सुवण क्षेत्र में मृदा संरक्षण ।
2. बाढ़ प्रवण नदी के सुवण क्षेत्र में समेकित पनधारा प्रबन्ध ।
3. झूम खेती का नियंत्रण ।
4. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के डकैती-प्रवण क्षेत्रों में बिहड़ सुधार कार्यक्रम ।
5. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में क्षारीय मृदा का सुधार ।

1990-91 के दौरान 0.28 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार के लिए 94.90 करोड़ रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी गई है । योजना आयोग द्वारा मृदा और जल संरक्षण योजनाओं के सम्बन्ध में आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप दिया जाना शेष है ।

छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव

3717. **श्री अनन्तराय देवशंकर दूबे** :
श्री प्रभाकर राव कलवला :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के कब तक प्रारम्भ कर दिए जाने की संभावना है तथा इस कार्य में कितना समय लगेगा;

(घ) इस कार्य में कितनी धनराशि व्यय होगी;

(ङ) आन्ध्र प्रदेश में इस समय छोटी और बड़ी लाइनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) बड़ी लाइन-3374 कि. मी., मीटर लाइन-1610 कि. मी. ।

(च) आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए संसाधनों की तंगी के कारण ।

Reservation for Backward Classes and Harijans in Armed Forces

3718. SHRIMATI VEENA VERMA :
SHRI KAPIL VERMA :

Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether the provision for reservation for backward classes and Harijans are proposed to be extended to persons of these categories in armed forces;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN) : (a) to (c) There is no proposal under consideration of the Government to extend reservation for Other Backward Classes and Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Armed Forces.

Economic Freedom to Women

3719. SHRIMATI VEENA VERMA :
SHRI KAPIL VERMA :

Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether in the view of social and economic backwardness of women and with a view to help them the achievement of economic freedom; whether Government propose to grant a certain percentage of women in the services; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF WELFARE (SMT. USHA SINHA) : (a) and (b) The Department of Personnel and Training has under consideration a proposal to provide reservation for women in certain appropriate vocations/services in the Government.

Implementation of Bachawat Wage Board Recommendations

3720. SHRIMATI VEENA VERMA :
SHRI KAPIL VERMAN :

Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) what is the number of newspapers establishment in the country, State-wise, which have not so far implemented the Bachawat Wage Board recommendation and also those which have implemented the same partly;

(b) what are the measures being taken to force the defaulters to implement the recommendations; and

(c) whether any penal measures are under Government's consideration in this regard; if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN) : (a) A statement is enclosed. (*See* below).

(b) The State Governments are responsible for enforcement of the Bhachawat Wage Board's recommendations. All the State Governments have been addressed to enforce the implementation of these recommendations and take appropriate action against defaulters.